## The Pioneer

the pioneer
LUCKNOW | WEDNESDAY | NOVEMBER 14, 2018

# Concern over deaths of kids in road mishaps

PIONEER NEWS SERVICE ■ LUCKNOW

As Children's Day nears, Consumers' Guild has urged the government to save those on the roads by passing the Motor Vehicles Amendment Bill-2017 in the forthcoming winter session of Parliament. In 2017, more than 9,000 children had died in road accidents in India comprising 6.4 per cent of all the road users who died in road casualties. The number of injuries to children in road mishaps are also increasing every year.

"Children are the future of our young nation and their safety and protection should be the country's top priority. Road crashes are impacting children directly, including their ability to attend school. One reason children are more severely impacted by road traffic crashes is their limited physical, cognitive and social behaviour which makes them more vulnerable road users than adults and susceptible to serious injury or death as a result of road crashes," said Abhishek Srivastava from the Consumers' Guild. India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50 per cent by 2020.

"This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law. The Motor Vehicles Amendment Bill, 2017, has already been cleared by the Lok Sabha in April 2017 and is due for passage by the Rajya Sabha.

It is about time that we declare 'road safety a national priority' considering the fact that more than 400 people are dying on roads daily which is largely preventable," he said.

Consumer VOICE is leading a National Coalition of Road Safety which includes other organisations working on this issue. This National Coalition has been appealing to the Prime Minister and Union Minister of Road Transport and Highways for enhancing road safety for many months now. "If this Road Safety Bill is further deferred we will be putting at risk more precious lives before the next session of Parliament can adopt it. These casualties may include thousands of innocent children and youths in their productive years of life. The passage of this bill is crucial in the forthcoming winter session," said Abhishek Srivastava.

The Consumers' Guild has been working on road safety since long and has submitted various representations to Central and state governments for bringing a strong law on road safety besides organising various educational activities. Some of the key provisions of the proposed bill include making safety belt or a child restraint system mandatory in a car for children below 14 years of age with a stiff penalty of Rs 1,000. A guardian or owner shall be deemed to be guilty with Rs 25,000 penalty or 3 years' imprisonment with cancellation of registration of the vehicle for juvenile drivers and a penalty of Rs1,000 and subsequent disqualification of driving licence for not wearing a helmet. As per the annual publication, 'Road Accidents in India-2017,' a report released by the Ministry of Road Transport and Highways, there were a total of 4,64,910 road accidents, 1,47,913, road traffic deaths and 4,70,975 injured persons in the year 2017.

## Dainik Jagran

# मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित हो

जासं, चंडीगढ़ : बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए। यह कहना है कि स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस का। संगठन ने सरकार से मांग की है कि वह मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित कर कड़े नियम लागू करें। लोस में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तमाम बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। एनजीओ के अशीम सान्याल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाज और सरकार के लिए शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाना है और यह मजबूत सड़क सुरक्षा कानूनों के लागू होने पर ही किया जा सकता है। असीम ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 'रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया – 2017' के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 घायल हुए।

**Aaj Samaj**

# हादसों में बच्चों की क्षति सरकार के लिए शर्मनाक

**आंकड़े**

- बाल दिवस पर स्वयं सेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस का आह्वान
- मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2017 जल्द पारित करे सरकार

आज समाज नेटवर्क

**चंडीगढ़।** बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर स्वयं सेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने सरकार से आह्वान किया है कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2017 को राज्यसभा में पारित कर कड़े नियम लागू करें। लोक सभा में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। वर्ष-2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में नौ हजार से भी अधिक बच्चे अपनी जान खो चुके हैं तथा दुर्भाग्यवश इन आंकड़ों में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। एनजीओ के अशीम सान्याल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाज और सरकारों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। असीम ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया-2017 के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 घायल हुए।

**Ajit Samachaar**

# बाल दिवस पर मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित करने का आह्वान

चंडीगढ़, 13 नवम्बर (पठानिया) : बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर स्वयं सेवी संगठन - कंज्यूमर वॉयस ने सरकार से आह्वान किया है कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित कर कड़े नियम लागू करें। लोक सभा में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। वर्ष 2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में नौ हजार से भी अधिक बच्चें अपनी जाने खो चुके हैं तथा दुर्भाग्यवश इन आंकड़ों में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है।एनजीओ के अशीम सान्याल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहियें। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाज और सरकारों के लिये बड़ी शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाना है और यह मजबूत सड़क सुरक्षा कानूनों के लागू होने पर ही किया जा सकता है। इससे पूर्व लंबे समय से सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे विभिन्न संगठन इस विधेयक को पारित करने की दिशा में ज्ञापन सौंप चुके हैं।

असीम ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट 'रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया - 2017' के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनायें हुई जिसमें 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 घायल हुए।

**Divya Himachal**

एक नजर

## वाहन संशोधन विधेयक पास करे राज्यसभा

चंडीगढ़–बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस ने सरकार से आह्वान किया है कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित कर कड़े नियम लागू करें। लोक सभा में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। वर्ष 2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में नौ हजार से भी अधिक बच्चें अपनी जाने खो चुके हैं तथा दुर्भाग्यवश इन आंकड़ों में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। एनजीओ के अशीम सान्याल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाज और सरकारों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाना है और यह मजबूत सड़क सुरक्षा कानूनों के लागू होने पर ही किया जा सकता है। इससे पूर्व लंबे समय से सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे विभिन्न संगठन इस विधेयक को पारित करने की दिशा में ज्ञापन सौंप चुके हैं। असीम ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया . 2017 के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 घायल हुए।

**Daily Pioneer**

## NGOS URGE GOVT TO SAVE CHILDREN ON ROADS ACCIDENT

**Chandigarh:** Committed towards the safety towards children, the Consumer Voice has urged the Government to save children on road accidents by passing the Motor Vehicle Amendment Bill-2017. "More than 9,000 children died in road casualties in India comprising 6.4 percent of all road users who died in road casualties. Unfortunately, these figures are increasing every year. If this road safety bill is further deferred, we will be putting at risk more precious lives before the next session of the Parliament can adopt it," said Ashim Sanyal of Consumer Voice.

**Dainik Jagran**

## मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित हो

जासं, चंडीगढ़ : बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर सरकार को प्रभावी कदम उठाना चाहिए। यह कहना है कि स्वयंसेवी संगठन कंज्यूमर वॉयस का। संगठन ने सरकार से मांग की है कि वह मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित कर कड़े नियम लागू करें। लोस में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तमाम बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। एनजीओ के अशीम सान्याल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाज और सरकार के लिए शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाना है और यह मजबूत सड़क सुरक्षा कानूनों के लागू होने पर ही किया जा सकता है। असीम ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 'रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया – 2017' के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 घायल हुए।

**Dainik Savera**

## बाल दिवस पर मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित करने का आह्वान

**चंडीगढ़ (राकेश) :** बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बाल दिवस के अवसर पर स्वयं सेवी संगठन, कंज्यूमर वॉयस ने सरकार से आह्वान किया है कि वे मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा में पारित कर कड़े नियम लागू करें। लोकसभा में यह पास हो जाने के बाद यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। 2017 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 9 हजार से भी अधिक बच्चे जाने खो चुके हैं तथा दुर्भाग्यवश इन आंकड़ों में साल दर साल बढ़ौतरी होती जा रही है। एन.जी.ओ. के अशीम सान्याल ने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिएं। सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की क्षति समाज और सरकारों के लिये बड़ी शर्मनाक बात है। भारत ने सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किऐ हैं जिसका लक्ष्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी की कमी लाना है और यह मजबूत सड़क सुरक्षा कानूनों के लागू होने पर ही किया जा सकता है। इससे पूर्व लंबे समय से सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे विभिन्न संगठन इस विधेयक को पारित करने की दिशा में ज्ञापन सौंप चुके हैं। असीम ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट एक्सीडैंट्स इन इंडिया 2017 के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनायें हुई जिसमें 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 घायल हुए।

**Yugmarg**

# NGO urges govt to save children on road accidents

CHANDIGARH, NOV 13

Committed towards the safety towards Children day, Consumer Voice has urged the Govt to save children on road accidents by passing the motor vehicle amendment bill 2017. More than 9,000 children died in road casualties in India comprising 6.4% of all the road users who died in road casualties. Unfortunately, these figures are increasing every year. India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50% by 2020. This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law. The Motor Vehicles Amendment Bill 2017 has already been cleared by Lok Sabha in April, 2017 and is due for passage by the Rajya Sabha. "If this road safety bill is further deferred, we will be putting at risk more precious lives before the next session of the Parliament can adopt it. These casualties may include thousands of innocent children and youth in their productive years of life. The passage of Bill is crucial in the upcoming winter session" said Ashim Sanyal of Consumer Voice. "As per the annual publication 'Road Accidents in India-2017' a report released by Ministry of Road Transport & Highways there were a total of 4,64,910 road accidents, 1,47,913, road traffic deaths and 4,70,975 persons injured in the year 2017 " said Sanyal.

**Dainik Bhaskar**

दैनिक भास्कर

भोपाल, बुधवार 14 नवंबर, 2018

# मध्यप्रदेश

dainikbhaskar.com

दैनिक भास्कर, भोपाल, बुधवार 14 नवंबर, 2018

**रिपोर्ट** • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का खुलासा, सड़क सुरक्षा नीति बेनतीजा

## सड़क हादसों में मध्यप्रदेश में 962 बच्चों की मौत, देश का तीसरा राज्य बना हमारा प्रदेश

विशाल त्रिपाठी | भोपाल

सड़क हादसों में मौत का शक कम करने के लिए चल रही कवायद के बीच मध्यप्रदेश में वर्ष 2017 में 10,177 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वर्ष 2016 में मौत का ये आंकड़ा 9646 पर ही सिमट गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में बच्चों (18 वर्ष से कम) की मौत का चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वर्ष 2017 में मप्र के भीतर हुए सड़क हादसों में 962 बच्चों की मौत हो गई। इस आंकड़े के साथ मप्र देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसमें सबसे ज्यादा सड़क हादसों में बच्चों की मौत हुई है। इससे पहले उप्र और सिक्किम का नाम आता है। ये विश्लेषण नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एन्वॉयरमेंट (एनसीएचएसई) ने किया है। बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को वर्ष 2016 में निर्देश जारी किए थे। कहा था कि सड़क सुरक्षा नीति बनाकर सभी राज्य सड़क हादसों में दो फीसदी की कमी लाएं फिर इसी नीति को ध्यान में रखकर आने वाले दो वर्षों यानी 2018 तक सड़क दुर्घटनाएं 50 फीसदी तक कम करें। नीति के तहत पुलिस, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय की गई, जो केवल कागजी ही साबित हो रही है।

### वर्ष 2017 में 10,177 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में गंवाई जान, वर्ष 2016 में 9646 हुई थी मौतें

| | |
|---|---|
| प्रदेश में कुल सड़क हादसे | 57532 |
| घायल हुए | 53399 |
| मौत | 10177 |
| 18 वर्ष से कम उम्र के | 962 |
| 19-35 वर्ष के | 5303 |
| 35-60 | 3352 |
| 60 से ज्यादा | 560 |
| अन्य उम्र के | 4848 |

#### उप्र, सिक्किम में सबसे ज्यादा बच्चों ने जान गंवाई

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा उप्र में सामने आया है। वर्ष 2017 में भारत में 9000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, जो कुल मौत का 6.4 फीसदी है। इनमें सबसे ज्यादा उप्र और सिक्किम में 11.5 फीसदी बच्चों की जान चली गई। मप्र में ये आंकड़ा 9.5 फीसदी है।

#### सड़क पर पैदल चलने वाले भी महफूज नहीं

प्रदेश की सड़क पर पैदल चलने वाले 1280 लोगों की हादसे में मौत हो गई। दो पहिया सवार 3733 और चार पहिया सवार 1692 लोगों ने प्रदेश की सड़कों पर अपनी जान गंवा दी। बड़े वाहनों ने 1657 लोगों को मार डाला है।

#### राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित हो सड़क सुरक्षा

एनसीएचएसई के डायरेक्टर जनरल प्रदीप नंदी ने कहा कि यह उचित समय है कि सरकार हादसों में हो रही मौत के बढ़ते आंकड़ों को ध्यान में रखकर सड़क सुरक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करे। उन्होंने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2017 पारित करने की मांग भी की है।

#### राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने हादसों में मौत की दस वजह बताई

राजधानी में वर्ष 2017 में कुल 3393 सड़क हादसे हुए। इनमें 252 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भोपाल ट्रैफिक पुलिस की हालिया रिसर्च में इन हादसों की 10 प्रमुख वजह सामने आई हैं। इनमें से आठ कारणों में से ड्राइवर की गलती, पैदल चलने वाले की गलती, सवारी की गलती, गाड़ी की खराबी, रोड इंजीनियरिंग की खामी, खराब रोड, आवारा मवेशियों का सड़क पर होना, अन्य कारण रहे। हालांकि, 288 एक्सीडेंट ऐसे थे, जिनमें 39 लोगों की मौत हो गई, लेकिन पुलिस इन हादसों की वजह ही पता नहीं कर सकी है।

**D.B.Post**

DB POST

14 NOVEMBER | 2018

# MP records second-highest no. of kids' deaths in road accidents

## As per a ministry report, 962 children died in accidents in 2017

DB Post Correspondent

**Bhopal:** Madhya Pradesh recorded second highest number of deaths of children due to road accidents, according to the report Road Accidents in India-2017 issued by Union Ministry of Road Transport and Highways.

According to the report, in 2017, 962 children below 18 years of age died in road accidents in MP. The maximum in country was in Uttar Pradesh at 2,317.

Also, among all the deaths in road accidents, the percentage of children's death in MP is also second highest in country at 9.5% (962 out of 10,177). In UP and Sikkim, children's deaths made for 11.5% each of the total accidental deaths.

### PROVISIONS OF THE MOTOR VEHICLES BILL

- **Safety belt** for people below 18 years or child safety mechanism lest Rs1,000 will be charged as fine.
- **If a** driver is found to be a minor, then parents or owner of the vehicle will be held liable and Rs25,000 will be charged as penalty, including three years of imprisonment.

Citing these figures, the NGO National Centre for Human Settlements & Environment has urged the government for a quick passage of Motor Vehicle amendment bill. The bill was passed by Lok Sabha in April 2017, but is pending in Rajya Sabha. Retired DGP Arun Gurtu said if the bill takes more time to be passed it will jeopardise many more young lives.

**The Times of India**

THE TIMES OF INDIA, BHOPAL
WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018

# 1 out of every 10 killed in road accident in MP is child: Report

TIMES NEWS NETWORK

**Bhopal:** Calling for measures to make roads safer for children, Bhopal-based National Centre for Human Settlements and Environment (NCHSE) has demanded that government makes safety belt or child restraint system mandatory in a car for children, guardian/owner of vehicle should be held responsible for juveniles' driving.

Citing a Union government report on Children's Day, NCHSE, an NGO, has highlighted that third highest road accidents take place in MP. Last year, 57,532 road accidents occurred in the state resulting in 10,177 deaths and 53,399 injuries.

**Last year, 57,532 road accidents occurred in the state resulting in 10,177 deaths and 53,399 injuries**

Every 10th person losing life in a road accident in the state is a child. Last year, 2,317 children died in road accidents in the state.

For every one lakh people, 18 die each year in road accidents. In India, one death occurs every 3.5 minutes due to road accidents. On this Children's Day (November 14), the NCHSE urges government to save children on roads by passing the motor vehicles amendment bill 2017 in upcoming winter session of parliament.

"If this road safety bill is further deferred, we will be putting at risk more precious lives before next session of Parliament can adopt it. These casualties may include thousands of innocent children and youth in their productive years of life and the cost to the nation could be enormous. The passage of Bill is crucial in winter session," said Arun Gurtoo, former DGP.

India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50% by 2020. This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law, according to a press release by NCSHE.

## The Assam Tribune

The Assam Tribune
Guwahati, Wednesday, November 14, 2018

# Plea to pass motor vehicle bill in Parliament winter session

STAFF REPORTER

GUWAHATI, Nov 13: On the eve of Children's Day, the Consumers' Legal Protection Forum has appealed to the Central government to pass the Motor Vehicles Amendment Bill 2017 in the winter session of Parliament.

If this road safety bill is further deferred, more precious lives will be at risk. The casualties may include thousands of innocent children and youth in their productive years of life. The passage of the bill in the upcoming winter session is crucial, said Ajoy Bazaliya, advocate and secretary, Consumers' Legal Protection Forum.

In 2017, more than 9,000 children died in road casualties in India comprising 9.4 per cent of all who died in road mishaps. The number of children getting injured in road mishaps is also increasing every year, the Forum stated.

Road crashes are impacting children directly, including their ability to attend school. One reason why children are more severely impacted by road traffic crashes is their limited physical, cognitive and social behaviour, which makes them more vulnerable than adults and susceptible to serious injury or death as a result of road accidents.

"India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50 per cent by 2020. This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law. The Motor Vehicles Amendment Bill 2017 has already been cleared by Lok Sabha in April 2017 and is due for passage by the Rajya Sabha," the Forum stated.

It is high time road safety was declared a national priority considering the fact that more than 400 people are dying on roads daily, which are largely preventable, the Forum said.

Consumer VOICE is leading a National Coalition of Road Safety, which includes other organisations working on road safety such as Parivar, CUTS International, and Citizen Consumer and Civic Action Group (CAG). This national coalition has been appealing to the Prime Minister and Union Minister of Road Transport & Highways for enhancing road safety for many months now.

The bill proposes to make safety belt or child restraint system mandatory in cars for children below 14 years, with the provision of a penalty of Rs 1,000. Moreover, the guardian or the owner shall be deemed guilty with Rs 25,000 penalty and/or three years' imprisonment with cancellation of registration of vehicle for juvenile drivers.

As per the annual publication Road Accidents in India 2017, a report released by the Ministry of Road Transport & Highways, there were a total of 4,64,910 road accidents, 1,47,913 road traffic deaths and 4,70,975 persons injured in the year 2017 alone.

## Dainik Purvodaya

दैनिक पूर्वोदय

13 November 2018 Tuesday

## बाल दिवस पर संसद के शीत सत्र में मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2017 पारित करें

प्रस्तावित विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधान

1. यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या बाल प्रतिरोध प्रणाली को अनिवार्य बनाने और इसके लिए 1000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव करता है।
2. नाबालिग चालक होने पर अभिभावक/वाहन मालिक दोषी माने जाएंगे और वाहन का पंजीकरण रद्द होने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना और/या 3 वर्ष की जेल की सजा होगी।
3. हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा और इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

■ बच्चों को बचाने के लिए सरकार से उपभोक्ता संस्थानों का आग्रह

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट 'रोड एक्सिडेंट्स इन इंडिया-2017' के अनुसार वर्ष 2017 में कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुई। सड़क हमला जनित 1,47,913 मौतें हुई और 4,70,975 लोग घायल हुए।

# Northeast Today

Northeast Today

Redefining Northeast

## Appeal Made to Pass Motor Vehicles Amendment Bill

By NET Bureau, November 14, 2018

The Consumers' Legal Protection Forum on Tuesday appealed the Central government to pass the Motor Vehicles Amendment Bill 2017 in the winter session of Parliament.

"If this road safety bill is further deferred, more precious lives will be at risk. The casualties may include thousands of innocent children and youth in their productive years of life. The passage of the bill in the upcoming winter session is crucial," said Ajoy Hazarika, advocate and secretary, Consumers' Legal Protection Forum.

In 2017, more than 9,000 children died in road casualties in India comprising 6.4 per cent of all who died in road mishaps. The number of children getting injured in road mishaps is also increasing every year, the Forum stated.

Road crashes are impacting children directly, including their ability to attend school. One reason why children are more severely impacted by road traffic crashes is their limited physical, cognitive and social behaviour, which makes them more vulnerable than adults and susceptible to serious injury or death as a result of road accidents.

"India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety which aims to bring down road accidents by 50 per cent by 2020. This can only be achieved by having a stricter and stronger road safety law. The Motor Vehicles Amendment Bill 2017 has already been cleared by Lok Sabha in April, 2017 and is due for passage by the Rajya Sabha," the Forum stated.

It is high time road safety was declared a national priority, considering the fact that more than 400 people are dying on roads daily, which are largely preventable, the Forum said.

Consumer VOICE is leading a National Coalition of Road Safety, which includes other organisations working on road safety such as Parisar, CUTS International, and Citizen Consumer and Civic Action Group (CAG). This national coalition has been appealing to the Prime Minister and Union Minister of Road Transport & Highways for enhancing road safety for many months now.

The bill proposes to make safety belt or child restraint system mandatory in cars for children below 14 years, with the provision of a penalty of Rs 1,000. Moreover, the guardian or the owner shall be deemed guilty with Rs 25,000 penalty and/or three years' imprisonment with cancellation of registration of vehicle for juvenile drivers.

As per the annual publication Road Accidents in India-2017, a report released by the Ministry of Road Transport & Highways, there were a total of 4,64,910 road accidents, 1,47,913 road traffic deaths and 4,70,975 persons injured in the year 2017 alone.